MR. SPEAKER: The Minister wants it to be taken up at 2 o'clock. He is not yet ready.

SHRI VASANT SATHE: The practice has been to give us the statement in advance so that we may be ready to participate better.

MR. SPEAKER: Mr. Shanti Bhushan, have you any information to give now?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): I am making a statement at 2 o'clock.

MR. SPEAKER: You are not circulating it?

SHRI VASANT SATHE: We must go by the practice of the House, namely, a copy of the statement is given, at least half an hour earlier, to the member who has given the notice so that he may be ready to participate in the discussion.

MR. SPEAKER: Because it is not ready, they are asking for time. They are getting the information or something is happening, in between. Therefore, they have asked for time. If it is not ready, how can they circulate it?

SHRI VASANT SATHE: I do not mind its being taken up at 2 o'clock. But by 1.30 let me have a copy of the statement.

12.20 hrs.

GENERAL BUDGET 1977-78—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. SPEAKER: Shri Satyanarayan Rao was speaking yesterday. He may continue.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : अध्यक्ष जी, कल एक मिनट में मैंने जो कुछ भी कहा था, बजट के मुताल्लिक कहा था। जनता पार्टी के पावर में आने के बाद यह पहला बजट है—जनता यह उम्मीद कर रही थी कि यह बहुत डाइनेमिक बजट होगा, बहुत अच्छा बजट होगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा—लेकिन दुख है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता पर्टी में जितनी भी पार्टियां मिली हुई हैं, जैसे समुद्र में बहुत सी नदियां आकर मिल जाती हैं, उसी तरह से वे पार्टियां इसमें आकर मिल गई हैं। इस समुद्र में मिलने से पहले उनकी जितनी आइडयोलाजीज थीं, जैसे सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र भी थे, दूसरे लोग थे, वे सब अपनी-अपनी आइडयोलोजीज को भूल गईं। कम से कम हम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि सोशलिस्ट पार्टी वहां मिलने के बाद इस तरह का कैपिटिलिस्टिक बजट पेश करेगी। यह बहुत ताज्जुब की बात है। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पार्टी को, पूरे हिन्दुस्तान की गरीब जनता को इससे बहुत निराश हुई है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कल पटनायक साहब ने यहां भी भाषण दिया था और राज्य सभा में भी भाषण दिया था। यहां भाषण देते हुए उन्होंने कहा था—चूंकि पटेल साहब कुछ नहीं बोल सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है, कूव्वत नहीं है कि सुब्रह्मण्यम साहब का जवाब दे सकें, इसलिये मुझे इस डिबेट में इटरवीन करना पड़ा है। उन का पूरा भाषण बजट के ऊपर नहीं था, सिर्फ सुब्रह्मण्यम साहब के खिलाफ अटेक था। हर सेन्टेंस में वह सुब्रह्मण्यम-सुब्रह्मण्यम कहते रहे और खत्म भी उन्होंने सुब्रह्मण्यम साहब के नाम से किया। वह इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं, अगर होते तो ज्यादा अच्छा था।

[अध्यक्ष जी, जनता पार्टी में आने से पहले जो लोग कांग्रेस पार्टी में थे—जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी, जो 23 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, इसी में पैदा हुए, इसमें फले फूले, मुख्य मंत्री रहे, सेन्टर में बड़े-बड़े पोर्टफोलियोज उन्होंने होल्ड किये, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

रहे, आज वह कहते हैं कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, खराब किया, हिन्दुस्तान को तबाह कर दिया। न सिर्फ श्री मोरार जी देसाई, बल्कि उनके दूसरे साथी—चन्द्र शेखर जी, मोहन धारिया जी, जगजीवन राम, बहुगुणा जी, पार्लियामेंटरी अफेअर्स के मिनिस्टर रविन्द्र वर्मा जी, रामचन्द्रन जी, सब के सब अपनी पिछली बातों को भूल गये—यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। पिछले दो सालों में हम से कुछ गलती हो गई है—उस को तो मैं मान सकता हूं, लेकिन यह कह देना कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, देश को बरबाद कर दिया—यह बात ठीक नहीं है। जनता पार्टी तो अभी पैदा हुई है—उसके लिये कहना कि जनता पार्टी ऐसा करेगी, वैसा करेगी, पूरे हिन्दुस्तान को ले जाकर आकाश में पहुंचायेगी—ऐसी बात न कीजिये। पहले भी जब मैं यहां था, जब मेरे कई साथी इस तरह की बात बोलते थे तो मैं उनको भी ऐसा कहता था कि ऐसा मत बोलिये, कभी हमको इस तरफ भी आना पड़ सकता है, जिम्मेदारी की बात कीजिये। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप गैर जिम्मेदारी की बात न बोलिये, जिम्मेदारी की बात कीजिये। आज लोगों को आप से बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं—आज जनता पार्टी जो पावर में आई है वह आप लोगों की कुरबानियों की वजह से नहीं आई है, हमारी कुछ गलतियों की वजह से आई है। In politics there is no *mat dan*: there is only suicide. यह मैं मानता हूं कि हमने डेफनीटली गलती की है और गलती करके खुदकशी की है और इसीलिए आज हम इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जब इस लोक सभा का पहला सेशन शुरू हुआ था, तो हमारे लीडर श्री वाई० बी० चव्हाण ने कहा था कि हमारा कन्स्ट्रक्टिव कोआपरेशन रहेगा और हम रेस्पोंसीबिल अपोजीशन की तरह से काम करेंगे। हम लोग इधर बैठ कर कोई इस तरह की बातें नहीं करेंगे जैसे पहले कुछ उधर बैठने वाले लोग करते थे। बड़ी गैर-जिम्मेदारी की बातें वे करते थे। श्री राज नारायण भी ऐसी ही बातें करते थे और आज जबकि वे मंत्री हो गये हैं, फिर भी ऐसे ही बोलते हैं जैसेकि अपोजीशन लीडर की तरह हों। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा जिम्मेदारी से बात करें और कुछ काम करिये। हम आपको कोआपरेशन देने के लिये तैयार हैं। ये जो आए दिन आप फिजूल की बातें करते हैं, वे न करिये। रोजाना कमीशन बैठाने की बातें होती हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कब तक चलता रहेगा। इसके पहले के सेशन में और इस सेशन में भी हम रोजाना देखते हैं कि कुछ न कुछ आता ही रहता है, कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ और कभी संजय गांधी के खिलाफ। क्या इनके सिवा आपके पास कुछ करने को नहीं है।

श्री मधु लिमये (बांका) : सैकड़ों लोगों को मरवा दिया।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इसीलिए तो हम लोग आज इधर बैठे हुए हैं। वरना कोई वजह न थी कि हम उधर न बैठते।

श्री शिवनारायण (बस्ती) : जरा अपने स्पीकर साहब को देख लीजिये।

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप बैठ जाइए। फालतू बातें मत करो। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जरा जिम्मेदार बनें। अगर आप गैर-जिम्मेदारी से बोलेंगे तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। हम यहां पर 153 हैं। इससे पहले 10 लोग अपोजीशन में रह कर न्यूसेंस क्रिएट किया करते थे। हम तो 153 सदस्य हैं। हम चाहें तो हम भी वैसा ही कर सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप बैठ जाइए और बीच में दखल मत दीजिए। मैं यही बोलना चाह रहा था कि ऐसी चीजें

नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश के वास्ते आप को कुछ करना चाहिए। इसके लिए हम कोआपरेशन देने के लिए हमेशा तैयार हैं।

दूसरी बात जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कांग्रेस की जो एकोनामिक पालिसी है, उसमें कोई गलती नहीं रही है। पोलीटीकली हमने जरूर कुछ गलतियां की हैं। अब वे चाहे एक आदमी ने की हों या दो आदमियों ने की हों, मैं मानता हूं कि हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं और एक आदमी के लिए ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एकोनामिक पालिसी अपनाई वह खराब है, या लोगों ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। इस गलतफहमी में आप मत रहिये। कांग्रेस की जो एकोनामिक पालिसी है, वह बहुत साउण्ड है और बहुत हैल्थी एकोनामी कांग्रेस ने आप के हाथ में दी है और ऐसी बात नहीं जैसा कि कल श्री पटनायक साहब कह रहे थे। सुब्रह्मण्यम साहब ने परसों अपना भाषण करते हुए कहा था कि यह आपकी खुशकिस्मती है कि दो साल पहले जो एकोनामी इतनी खराब हो गई थी, उसको इतना अच्छा करके, इतनी साउण्ड एकोनामी करके आप को दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस हालत में आपको एकोनामी दी गई है उसको आप बनाए रखेंगे और यह बहुत अच्छा होगा। कल जब श्री पटनायक साहब बोल रहे थे, तो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा था कि क्या साउण्ड एकोनामी दी है और सब सत्यानाश करके हम बैठे हैं। जिन्होंने पटेल साहब की बजट स्पीच को पढ़ा होगा, उन को पता होगा कि उन्होंने खुद माना है कि गुजिश्ता दो सालों में तरक्की हुई है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ लिया होगा लेकिन फिर भी मैं उसमें से कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि कल एक जिम्मेदार मिनिस्टर साहब यहां बोल रहे थे और कह रहे थे कि कोई साउण्ड एकोनामी नहीं है, कोई हैल्थी एकोनामी नहीं है :

"In the last two years, while India's exports have increased rapidly, imports during 1976-77 were restrained both on account of the bumper harvest of 1975-76 and increased domestic production of such critical inputs as fertilizers. The rapid increase in inward remitances has given added strength to India's balance of payments and our reserves have gone up considerably. Nevertheless, we would be foolish if we did not take note of the fact that our balance of payment still remains vulnerable to the effects of sudden shocks, such as harvest fluctuations. The current level of food stocks and foreign exchange reserve do give us wider options in the management of the economy than ever before. Foreign exchange reserves will have to be so deployed as to assist in the maintenance of price stability, as also in accelerating the process of growth."

उन्होंने यह माना कि पिछले दो साल के अन्दर क्या हुआ और जो पैसा है उसको वे यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो स्टेटमेंट है कि देश की एकोनामी खराब हुई है वह ठीक नहीं है। आपके हाथ में कांग्रेस सरकार ने 18 मीलियन टन फूड ग्रेन छोड़ा है। यह मामूली बात नहीं है। आप यह मत भूलिये कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप तीन साल भी यहां टिकने वाले नहीं हैं। हम यह जानते हैं कि एक साल के अन्दर क्या कुछ हो सकता है।

मैं कल मैं एक बात कह रहा था जिसको फिर दोहराना चाहता हूं। मैं अपने पटेल साहब से नाराज नहीं हूं। वे बहुत ईमानदार आदमी हैं और उनकी जो पालिसी आज तक रही, उसी पर वे अभी भी डटे हैं। मैं जानता हूं कि वे स्वतंत्रता पार्टी में रहे हैं और उस

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

पार्टी के जो ख्यालात सोशलिज्म के बारे में थे, वे उसी पर डटे हुए हैं। इसके लिए मैं उनको दोष नहीं देना चाहता। लेकिन हमारे जो दोस्त आज तक सोशलिज्म की बात करते रहे हैं, उनको चुप देखकर मैं हैरान होता हूं। हमारे सोशलिट दोस्त गरीबों की इस हाउस में बड़ी वकालत करते थे। वे कहा करते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट गरीब लोगों के बारे में कुछ नहीं कर रही है। लेकिन आज इस बजट में लेण्ड रिफार्म्स और लेबर बेजिज के बारे में कुछ न देख कर ताज्जुब करता हूं। क्या हुआ उन सब का जिनके बारे में हमारे जनेश्वर मिश्र और मधु लिमये बहुत कुछ कहा करते थे। आपने इस बजट में क्या किया? सिवाय इसके कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कंसेशन दे दिये हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और लेण्ड रिफार्म्स के वास्ते इस बजट में कोई प्राविजन नहीं किया गया। मेरे दोस्त जो सोशलिस्ट्स थे, वे आज जनता पार्टी में बैठे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आज वे चुप क्यों हैं? मैं समझता हूं कि इस तरह का बजट पेश करना न तो जनता पार्टी के वास्ते अच्छा है, न हिन्दुस्तान के वास्ते अच्छा है। आप लोग रूलिंग पार्टी में हैं, अब आप लोग गरीबों को उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने देश में गरीबों को नहीं उठाया तो यह मत भूलो कि आप यहां बैठे रहेंगे। देश में इंक्लाब आ जाएगा, हम तो तीस साल यहां बैठे रहे, आप तीन साल भी हकुमत नहीं कर सकोगे। जब हम गरीबी हटाओ की बात करते थे तो आप लोग हंसते थे। अब आप क्या गरीबी हटाओ का यह प्रोग्राम दे रहे हैं? मैं तो यह समझता हूं कि आप इस बजट में गरीबी नहीं हटा रहे हैं बल्कि गरीबों को हटाने का प्रोग्राम दे रहे हैं। मुझे इस बजट के बारे में अपने सोशलिस्ट दोस्तों को खामोश देख कर हैरानी होती है। आज जनेश्वर मिश्र खामोश बैठे हैं, हमारे दूसरे दोस्त खामोश बैठे हुए हैं।

मैं यहां जार्ज बर्नार्ड शाह की एक बात रिमाइण्ड कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

"If a person who is below 30 years of age does not believe in socialism, he has no heart, hut after forty years, if he still believes in socialism, he has no mind."

शायद इस बात को मेरे सोशलिस्ट दोस्त भी जानते होंगे। मैं समझता हूं कि वे लोग अब 40 साल से ऊपर के हो गये हैं इसलिए ऐसा मालूम होता है कि वे यह सोशलिज्म की बातें भूल गये हैं।

बजट देखने के बाद मुझे कुछ नहीं मालूम होता कि आप स्मगलर्स के वास्ते क्या करने जा रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि जितने स्मगलर हैं और ब्लैक मार्किट करने वाले हैं उन को कंट्रोल किया जाए। अभी तक आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की है।

राइमेसी आफ एग्रिकलचर के बारे में आप ने बहुत कुछ कहा है। आपने तो ऐसी बात कही जिससे यह ध्वनित होता है कि इससे पहले वाली कांग्रेस सरकार ने एग्रिकलचर के बारे में कुछ किया ही नहीं था। रोड्ज के बारे में, पोलटरी फार्म्ज, डेरी, वेजीटेबल, सरिकलचर, ड्रिंकिंग वाटर आदि पर जो आपने बहुत ज्यादा जोर दिया है उससे आपने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने इन क्षेत्रों में कुछ नहीं किया था। बीस सूत्री कार्यक्रम को आप देखें। उस में यही बातें थी, एग्रिकलचर से सम्बन्ध रखने वाली बातें थीं जिन पर सब से ज्यादा जोर दिया गया था। यह अलग बात है कि कुछ गलतियां हो गईं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीस सूत्री कार्यक्रम अच्छा नहीं था। आप जितना रूरल डिवेलेपमेंट करने की बात कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम ने किया था। अभी भी जो कांग्रेस सरकारें हैं वे भी कर रही हैं। आपको तो मालूम ही है कि इलैक्शन में किन लोगों ने आपको स्पोर्ट दी है। सब बड़े बड़े जमींदार लोग थे जिन्होंने आपको स्पोर्ट किया है। इसलिए जनता पार्टी आ सकी है। उनको यह भरोसा था कि अगर जनता पार्टी

आ गई तो उनके पास जो जमीनें हैं उनको वे रख सकते हैं । उन पर सीलिंग का कानून आगे लागू नहीं होगा । लैंड रिफार्म्ज की बात आपने निकाल ही दी है, उसका जिक्र तक नहीं किया है । आप लोग उनकी स्पोर्ट ले कर चल रहे हैं । यह अच्छी बात नहीं है । अगर इसी तरह से आप चलते रहे तो मैं कहता हूं कि देश में इनकलाब हो जाएगा और इससे न आपको फायदा होगा और न ही हम को होगा, इससे फायदा मार्क्सिस्ट दोस्तों को होगा, वही लोग इससे बैनिफिट उठा सकेंगे । इस वास्ते मैं अभी से आपको इसके बारे में वार्न कर देना चाहता हूं । लैंड रिफार्म्ज आदि पर आप अभी से ज्यादा ध्यान दें ।

इरिगेशन के बारे में मैं आपको दो चार सजेशंज ही देना चाहता हूं । आप तो जानते ही हैं कि तीस परसेंट लैंड ही अंडर इरिगेशन है, बाकी सत्तर परसेंट में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है । डा० के एल० राव ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था । जहां आपने इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की है उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि गंगा और कावेरी को मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा और वहां यह फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है ।

रिवर वाटर डिसप्यूट्स भी अभी तक कुछ पैंडिंग पड़े हुए हैं । कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ को हल कर दिया था । फिर भी अभी कावेरी का डिसप्यूट बाकी है । इसको तथा दूसरों को आप सैटल करने की कोशिश करें ।

मैं अब पावर के बारे में कहना चाहता हूं । रामचन्द्रन साहब बैठे हुए हैं यह खुशी की बात है । आंध्र प्रदेश की सरकार ने आपके पास पावर के बारे में एक रिक्वैस्ट भेजी है ।

Regarding super thermal power station at Ramagudam, plenty of labour is available there and Godavari water is there. The labour is very cheap and everything is available there. The only thing is that because of Congress Government there, You should not discriminate. I think, the hon. Minister will not discriminate. If this super thermal power station is establised there, not only the problem of solved. My request to the Minister Andhra but whole of south will be solved. My request to the Minister through you, is that he must see that this super thermal power station at Ramagudam is established.

डिफेंस एक्सपेंडिचर आपने 56 करोड़ कम कर दिया है । ऐसा करके आपने अच्छा नहीं किया । इससे पता चलता है कि श्री जगजीवन राम की कुछ नहीं चल रही है जनता पार्टी में । अगर चलती होती तो कोई कट न किया गया होता । उनका शीर्ष ही इससे कटा हुआ मालूम होता है ।

बजट स्पीच में आपने 21 करोड़ रुपये का कट लगाया जिसका बैक्वर्ड एरियाज में न्यू रेलवे लाइंज का विकास करने में असर पड़ेगा । इससे उनको नुक्सान पहुंचेगा । रेलवे में जो एलोकेशन पहले था उसको आप बहाल करें, इस कमी को आप पूरा करें ।

वाइजग स्टील प्लांट श्री पटनायक उड़ीसा में ले जाना चाहते हैं । यह ठीक नहीं है । इसी तरह से सुपर थर्मल पावर की बात है । अगर ये दोनों वहां न किए गए तो बहुत नाइंसाफी होगी और इसके खिलाफ बड़ा एजीटेशन होगा । अगर इस प्लांट को आप उड़ीसा में ले गए तो यह बड़ी भारी सैलफिशनैस होगी । यह एक नैशनल प्राजैक्ट है । इससे न सिर्फ आंध्र को फायदा होगा बल्कि सारे देश को होगा । यह ऐसी चीज है जिसको आप निगलैक्ट नहीं कर सकते हैं । अगर निगलैक्ट करेंगे तो आपको इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, यह मैं आपको आज वार्निंग देना चाहता हूं ।

[श्री एम०सत्यनारायण राव]

न्यूकलियर पावर स्टेशन के बारे में भी एक प्रोपोजल आंध्र प्रदेश से आई है। मैं समझता हूं कि आप ने एक्सपर्ट कमेटी भी कांस्टीट्यूट की है। इस सिलसिले में रिपोर्ट क्या हुई है उसको भी आप देखें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आटोमोबाइल टायर्स का जो प्रोजैक्ट है मंगलगिरि प्रोजेक्ट, इनको भी पूरा कीजिये। ऐग्रीकल्चर के बारे में जो रूरल सैक्टर में आपने कहा है अपनी स्पीच में कि पहली कांग्रेस सरकार ने इस सैक्टर को नैग्लैक्ट किया है, इस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऐलोकेशन आपने किया है वह 3,024 करोड़ है जब कि कांग्रेस सरकार ने इस पर 3,447 करोड़ रु० का ऐलोकेशन किया था। मतलब यह हुआ कि आपने 400 करोड़ रुपया इस सैक्टर में कम कर दिया। तो आप जो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और खादी पर हम काफी पैसा लगा रहे हैं वह तथ्य से दूर है। वास्तविकता यह है कि आप इस में कटौती कर रहे हैं।

MR. SPEAKER: Now, before I leave the Chair, I want to say something. The Congres party has exhausted all its time. But from the Speaker's time, I gave some time to Mr. Satyanarayan Rao. The CPI has not taken any time. The A.I.A.D.M.K. has also not spoken at all. The Janata Party has got 1 hour and 44 minutes. Some Members from their side also will be called. If they take 5 minutes each, a large number of Members can be accommodated. I am trying to explain the position for the guidance of the next Chairman.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam) Sir, on the first day, it so happened that one Member from the Government side and one from the Congress side were called. Yesterday, for one on our side two or three were called from the other side. They were not ready with their speakers on the first day. So, we were asked to speak. Many of us have now been prevented from speaking. In your discretion, You may give some more time to us.

MR. SPEAKER: It is not a question of the number of speakers but it is the time that is allowed. From the Congress side, the senior Members, the ex-Ministers and the ex-Chief Ministers have taken 30 to 40 minutes each. From the ruling party-side, they are making maiden speeches of 5 to 7 minutes each. The Speaker has got some spare time which can be given. But don't demand it. Nobody from the C.P.I. and the A.I.ADMK has spoken.

Now, I call Mr. Govindan Nair from the C.P.I. to speak. After him, the A.I.A.D.M.K. Member will speak. Then, the Janata Party Members will have 5 minutes each so that a large number of Members can speak from their side.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच): अध्यक्ष महोदय, आप जो समय अलाट करते हैं तो शुरू के स्पीकर अधिक समय ले जाते हैं और पीछे वालों के लिये 5, 5 मिनट का समय रह जाता है।

MR. SPEAKER: That is why I say it will be given now.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): I would like to make a brief submission and request that the time allotted may in line with what used to happen in the House from 1962-72 again be restored—that tradition may be restored. From 1962 to 1972, the time allotted for discussion on general debate used to be 20 hours. It was only after 1972 that it was reduced to 15 hours. Let us reverse that tradition and go back to the earlier tradition.

MR. SPEAKER: This time we have begun discussion on the Budget late because of elections all over the country. A number of demands will be guillotioned. If you want more general discussion, then some time is required. Yesterday, the Business Adisory Committee had discussed all these aspects and they had also accepted this schedule. Now Mr. Govindan Nair.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): Mr. Speaker, Sir permit me, at the outset, to congratulate the Janata Party on their glorious victory in the Lok Sabha as well as in the Assembly elections. Now they are comfortably settled on Government both at the Centre and in most of the States. The line is now clear for them to fulfil the promises they had made to the people. I am not blaming the Janata Party if they do not join the socialist creed. But they had assured the people that they would uphold the democratic values, they would reflect the Constitution both in words and spirit and they will follow the democratic norms in their functioning.

So I am judging them by what they had promised and I am sorry to note that inspite of the repeated assurances they have given—from the papers, all of you must have known—defections are being encouraged. A number of Lok Sabha, Rajya Sabha and Assembly Members are now crossing over to the Janata Party.

SHRI C. SUBRAMANIAM (Palam): Tempted to cross over.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: There are defections or an exodus, I do not know. But this goes very much against the assurances that the Prime Minister himself has given. It is a shame to convert our Assembly members into Aya Rams and Gya Rams. It was expected especially when the Prime Minister himself had made a categorical statement that he would never permit anybody to cross-over and join the Janata Party. Only a few days have passed since this statement was made and you can see what is happening now. Not only Lok Sabha and Rajya Sabha Members are crossing over, but the big news is that a number of MLAs are also crossing over to the Janata Party. This is something which is deplorable. The point is what the Prime Minister himself says today just the opposite happens the very next day. Where is the credibility? How are we to function? Therefore, I think steps should be taken to see that this kind of defections do not take place. I am interfering with the liberty of any person to join any political party, but if he wants to do so he should resign his membership of Legislative Assembly or of Parliament and then join another party. I hope the hon. Prime Minister will give attention to the point I have raise.

Secondly, I was very much amused that was taking place in this House between the Congress Party and the Janata Party. Mr. Subramaniam spoke for the Congress Party. Well, he knows that this Budget of the Janata Party was also made of the same mould which he had prepared except that it was disfigured by dropping certain basic features to give it the Janata look. That is all. In the main, we expected a new approach as they were saying that they were going to change the life of the rural people in this country. They said that they would eradicate poverty and unemployment. I am quite sure the Finance Minister did not consult even his colleagues when he prepared the Budget. I say this because they are speaking so much about unemployment, especially among the rural people. And what is the allotment that they have made? They have allotted Rs. 35 crores for khadi and village industries and Rs. 20 crores for handlom. He must be completely ignorant of the condition of the handloom workers or the handloom industry. If he were so, he could have

[Shri M. N. Govindan Nair]
consulted his friend and colleague, Mr. Charan Singh, who is an expert on handloom industry. The Finance Minister has allotted Rs. 20 crores for handloom. Does he know that the accumulated stock with the cooperatives and the weavers organized under them alone will cost more than Rs. 20 crores? They claim that they will give employment to 25 lakh people. Will they be able to maintain the existing weavers to carry on their work and make a living? The solution that the hon. Home Minister has been suggesting will finish off both handloom industry as well as the textile industry. I am not going into that now.

He has allotted Rs. 35 crores for khadi and village industries. Many a time the functioning of the khadi and village industries has been discussed in this House. I do not want to comment on it, but I can only say that, in spite of the tall talk they have made, nothing has been done to tackle the problem of unemployment. Now, they were speaking about allocation for development of agriculture. From the Report before us it is very clear that our main drain of foreign-exchange, even to this day, is in respect of agricultural products, for food—not only cereals but edible oils and pulses etc. All these things are sought to be got from other countries. We claim that our economy is agrarian but even today, after thirty years, we are in a position where we have to depend on other countries for our essential commodities. This state of affairs must change. When an emphasis or an over-emphasis was laid on this by the Janata leaders, I thought there would be sufficient provision at least to improve upon what the previous Governments were doing. They have said that agriculture should be modernised. Everybody knows that if you want to increase agricultural production, it should be modernised. That means there should be irrigation facilities there should be fertilisation, new hybrid variety of seeds should be used etc. Now, I ask you, is there any provision other than the normal one for increasing the utilisation of any of these things in the field of agriculture? You are speaking about poultry; you are speaking about dairying and, for all these things that you are speaking of, some money has already been allocated. But to make a radical change, has there been any change in the allocations? There is none. For approach roads, transport infrastructure etc., what is the allocation? Which are the new Railway lines we are going to open? Which are the new roads we are going to construct? I am sorry to say that for none of these vital things has sufficient allocation been made so as to effect a real change in the rural economy of the country.

If you want to change the rural life of the people, one important thing, which I forgot to mention, is land reforms. No mention of this has been made in this budget. Of course, I don't say that the word itself has not been mentioned: the word has been mentioned, but what is the provision in the Budget for taking up land reforms seriously? I come from a State where land reforms were implemented. Have you any idea of the number of landless people in this country? How are you going to solve their problems unless you enforce radical land reforms and distribute land to the cultivators? Speaking from my experience, lakhs of people in my State were destitutes and they have been provided with land. Unless the Janata Party takes up the question of land reforms seriously, they are not serious about the development in the rural sector.

13 hrs.

When you speak about the rural population and when my friends on the other side harp on democracy and democratic values, we have to see what is the state of affairs in the rural side. You and I become very eloquent and our moral indignation knows no bounds when we hear racial discrimination outside our country, but what is happening in your own vil-

lages? Do you treat the backward people in the villages, the Harijans as your equals? Bihar is the home State of Jayaprakash Narayan; this State is otherwise also very important. During the last one and a half years, the number of Harijans killed according to Government reports is 100 and the number of Harijan women raped is 75. The atrocities committed during the last few years have been increasing. In 1972, the number of cases of attrocities against the Harijans was 98, in 1973, it was 105, in 1974, it was 259, in 1975, it went upto 300 and in 1976, it was 1200. For the year 1977, the Government have not published the figures as yet, but we know, what has been happening in Bihar. You have read about how people were burnt to death in Bihar. The explanation given by the Home Minister was that it was a fight between two criminal gangs and they killed each other, but why is it that only Harijans were killed? Is that the only State with this situation? What about Gujarat, what about Andhra Pradesh and what about Tamil Nadu? You speak about democracy. Democracy for whom? For us, for the elite, not for the poor people?

If you want a change in the society, you have to raise the status of these people and protect them from the socially dominating section. I am sorry to say that after the Janata Government have come, the rural rich feel that it is their Government and their aggression on the poor section of the people is on the increase. I am not blaming any particular party for this state of affairs because we had inherited an undemocratic society. Centuries of tradition, sanctity of religion—all these are so deep-rooted that unless the entire people move against these and try to mould a democratic society out of our village people, all talk of democracy has absolutely no meaning. Therefore, if you want to make a change in the rural life of the people, the first thing is that you have to come forward with land reform. Secondly, you have to democratise the village society and thirdly you will have to find employment for them. Some people say that they are following Gandhian economics. Well, in my own way I have tried to understand Gandhiji. Gandhiji was murdered, physically murdered, but don't try to kill him spiritually also by saying that it is the Gandhian economics you are going to follow. When he raised the slogan of village industries, it was the time of the freedom struggle. When against the economic enslavement of the people of the country he had given a call, the spirit of the call was to struggle against the economic enslavement from the British imperialism and also develop a sense of self-reliance. If this spiritual Gandhian politics is forgotten, you are rejecting Gandhiji because I often heard that you are again restoring Gandhian values. How it has been worked out in villages, I have already told you. There also, in today's circumstances, if you want to build up your economy, if you want to solve the problem of unemployment, sticking on to village industries alone will never do. You have to have modern industries also. People here are speaking about Japan, about Sweden and say, 'Let us follow them'. But, have you studied their economy? Japan is one of the most highly industrially developed nations of the world. They are competing and defeating even the highly developed countries of the world and with the ancillary industries in the villages, they are providing jobs. Now, if you forget this and if you want to turn this nation into a hermit nation, you will not be able to survive.

Here also, the emphasis that the earlier governments have given on public undertakings is not there and what it means also one can understand. If you want to leave industries to the private sector, if you want to encourage them, well, that would be at the risk of industrial

[Shri M. N. Govinda Nair]
development. Well, if there is another occasion, I will speak about it.

Now, Sir, much is talked about these small scale industries. The small scale industries, just as in the case of others, are also talked about. But what is he provision in the budget? Now everybody is praising him for reducing the deficit. This reduction has been caused by shifting certain sectors. This is how the reduction was made.

I ask a question—can any small scale industry survive with the present rate of interest which has to be paid to the banks? There is a small percentage of the advance that they make which you can get at a lower rate of interest. Even that percentage has not been raised. According to the existing arrangement if you pay half a per cent of the advance, you get at a lower rate known as differential interest rate. But that is only for half a per cent. It will benefit only a very small percentage. Even that has not been changed.

I do not want to take much of the time. I only say that the assurance and promises that the Janata Party has made to the people of this nation are not at all reflected in this Budget and I am sure, unless a radical change in the entire approach is made, our country will head to an economic crisis.

MR. SPEAKER: We extend our discussion. The hon. Minister will reply to-morrow at about 15.30 hours.

श्री विजयकुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट को जनता पार्टी का बजट कह कर, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने और कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी ने जो वादे किये थे, जनता पार्टी ने जो उम्मीदें लोगों को दिलायी थीं उनका कोई रिफ्लेक्शन इस बजट में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी समझदार आदमी यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि इस बजट के अन्दर जो वादे जनता पार्टी ने किये, उनका पूरा रिफ्लेक्शन इस बजट के अन्दर हो सकता है। यह बजट सितम्बर, अक्टूबर, 1976 में बनना शुरू हुआ, जनवरी में इसको पूरा कर दिया गया। जनवरी में जो बजट कम्प्लीट कर दिया गया हो, क्या उस बजट में जून में कोई खास चेंजिज की जा सकती हैं? यह बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। क्या प्लान के फोर्थ इयर में, चौथे साल में कोई रेडिकल चेंजिज हो सकती थी। यह एक तरह से मुश्किल सी बात है, नामुमकिन सी बात है। क्या चौथे साल की कैरी ओवर स्कीम्स को बीच में छोड़ा जा सकता है, अधूरा छोड़ा जा सकता है? उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बजट कांग्रेस का बजट है, पिछले साल में तैयार किये गये बजट के मुताबिक इसको बनाया गया है। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में एक दिशा निर्देश दिया है जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

13.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

इन सर्कमस्टांसिज में, इन हालात में जबकि बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी, उनमें भी इस बजट में जनता पार्टी का रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की गयी है। सब से पहली इम्पार्टेंट बात इसमें यह है कि जो घाटा 632 करोड़ का एक्सपैक्टिड था उसको उन्होंने कम कर दिया है और उसको वह केवल 72 करोड़ पर ले आए हैं। पिछले बारह सालों में 1969—70 को छोड़ कर इससे कम घाटा कभी नहीं दिखाया गया। इतना कम घाटा दिखाने वाला जो बजट उन्होंने हमारे सामने रखा है यह कोई मामूली बात नहीं है। अब

इसकी जो आलोचना करते हैं उनके लिए मैं यही कह सकता हूं कि वे आलोचना करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। एक बात साफ है कि जनता पार्टी कीमतें कम करने के लिए घाटे की अर्थ व्यवस्था को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है और इसी दिशा में उसने अपनी एफर्ट्स का डायरैक्ट किया है।

सुब्रहमण्यम साहब तथा दूसरे दोस्तों ने कहा है कि यह कैपिटलिस्ट बजट है, पूंजीवादी बजट है, इस में पूंजीपतियों का पोषण किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो समाजवाद कांग्रेस हमारे देश में लाई थी उसको यह जनता सरकार खत्म न करे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवाद का नाम लेने की स्थिति में वे आज भी अपने आपको पाते हैं? क्या ऐसा कहते हुए उनको संकोच नहीं होता है या लज्जा का अनुभव नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीस साल में कांग्रेस के चार प्लांज के बाद भी क्या यह हकीकत नहीं है कि बड़े बड़े पूंजीवादी जो घराने है, कैपिटलिस्ट हैं, बिड़ला, टाटा हैं उनके यहां पर दौलत सौ-सौ गुना अधिक बढ़ गई है? जो लोग पचास करोड़ की मिलकियत के थे 1950 में आज वे 1800 करोड़ की मिलकियत वाले हो गए हैं। उसके साथ ही दूसरी तरफ चालीस परसेंट लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, सबसिस्टैंस लेवल के नीचे चले गए हैं। रेट आफ ग्रोथ सारे भारत में पिछले बीस साल में तीन परसेंट एवेज भी नहीं बैठता है जबकि बड़े बड़े मौनोपोली हाउसिस के एवेज रेट आफ ग्रोथ को आप देखें तो वह 18 परसेंट तक चला गया है। यह कांग्रेस के समाजवाद का नमूना है जिस ने केवल पूंजीवाद पैदा किया चाहे वह सरकारी पूंजीवाद हो या निजी पूंजीवाद हो। इसके बावजूद भी वे कहें कि वे समाजवाद लाना चाहते थे तो सिवाय आश्चर्य के कुछ नहीं होता है।

1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और जब सुब्रह्मण्यम साहब ने क्विट पावर्टी का नारा दिया उस समय हिन्दुस्तान के लाइव रजिस्टरों में कुल मिला कर 31 लाख लोगों के नाम, बेरोजगारों के नाम दर्ज थे। उसके बाद वह समाजवाद लाए और और उसका नतीजा यह है कि आज 1976 में पिछले साल प्लान के अन्दर जो आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक 97 लाख 84 हजार बेरोजगारों के नाम वहां दर्ज थे। इसका मतलब यह होता है कि तीन सौ परसेंट की उसके अन्दर बढ़ोत्तरी आज हो गई है। उसके बाद भी कोई समाजवाद की बात करे तो उन्हें क्या कहा जाए।

1976 में पांच लाख 20 हजार गांव देश में ऐसे थे जिन में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। तीस करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिन को प्राइमरी हैल्थ सेंटर की कोई सुविधा बीस मील के घेरे में उपलब्ध नहीं है। करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा सकते है, स्कूलों में उनकी पढ़ाई नहीं होती है और जो भीख मांगते हैं या जो छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। जनता पार्टी इस तरह की जो डिसपैरिटीज हैं जो समाजवाद के नाम पर यहां क्रियेट की गई है यकीनी तौर पर उनको खत्म करना चाहती हैं, भारत के माथे पर यह जो कलंक का टीका है इसको धोना चाहती है।

सब से बड़ी हैरानी की एक और बात है। कांग्रेस के बहुत से मित्रों तथा कम्युनिस्ट पार्टी के मैम्बरों ने चौधरी चरण सिंह की इस बात के लिए आलोचना की हैं कि उन्होंने कहा था कि वह भारत में काटेज इंडस्ट्रीज को, स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कंज्यूमर आइटम्ज हैं और जो काटेज इंडस्ट्रीज बना सकती है उनको बड़ी इंडस्ट्रीज के बनाने पर बैन लगा देना चाहिये। उनकी इस बात पर उनको बड़ी तड़पन हुई और उन्होंने

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

कहा कि इससे जो माडर्न नोहाऊ है वह खत्म हो जाएगा, भारत में बैकवर्डनेस आ जाएगी, भारत पीछे चला जाएगा। उनका तड़पना मेरी समझ में आता है। जिन पूंजीपतियों से करोड़ों रूपया ले कर जो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं जो उनके जर खरीद गुलाम हैं उनकी तरफ से पूंजीपतियों की वकालत न हो यह कैसे हो सकता था। उन पूंजीपतियों पर आज अगर चोट होती है तो इनका तिलमिलाना मेरी समझ में आता है।

एक दो फिगर मैं और देना चाहता हूं। पहले प्लान में स्माल स्केल इंडस्ट्री के वास्ते 4 करोड़ 20 लाख रुपया रखा गया था और बड़ी के वास्ते 6 करोड़ 50 लाख। यानी करीब करीब बराबर दोनों के लिए पहले प्लान में प्राविजन किया गया था। लेकिन 1976-77 में पिछले साल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज के वास्ते जहां प्लान में 95 करोड़ रखा गया वहां बड़ी इंडस्ट्रीज के वास्ते 2185 करोड़ रुपया रखा गया। बड़ी इंडस्ट्री को स्माल स्केल इंडस्ट्री से करीबन 20, 21 गुना प्रोवीजन 1976-77 में रखा गया। नेशनलाइज्ड बैंक्स ने बड़ी इंडस्ट्रीज को 90 परसेंट लोन दिया और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को 10 परसेंट लोन दिया। इम्पोर्ट लाइसेंस 1975-76 में छोटी इंडस्ट्री को 87 करोड़ के दिये गये जब कि बड़ी इंडस्ट्री को 620 करोड़ रु० के दिये गये। 10 परसेंट केवल इम्पोर्ट लाइसेंसेज छोटी इंडस्ट्री पर आये। छोटी इंडस्ट्री एम्प्लायमेंट देती है 60 परसेंट और बड़ी इंडस्ट्री देती है 40 परसेंट। लेकिन सारे लोन्स, इम्पोर्ट लाइसेंस स्कैरी रा-मैटीरियल बड़ी इंडस्ट्री 90 परसेंट ले जाती है। इसी कारण से गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर और अमीर होता चला गया। इस का एक ही रास्ता है कि देश देश में जितने कन्ज्यूमर्स आइटम्स हैं यह बड़ी इंडस्ट्रीज न बनायें बल्कि छोटे छोटे सैक्टर और काटेज इंडस्ट्रीज में बनें तभी देश के अन्दर से डिस्पैरिटी खत्म हो सकती है और इकोनामिक पावर का डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो सकता है। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़ी इंडस्ट्री की वकालत करते हैं और वर्ग संघर्ष के नाम पर उस को बनाये रखना चाहते हैं तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।

रेट आफ ग्रोथ जो चौथी प्लान में 28 परसेंट होनी चाहिये थी वह केवल 14 परसेंट हुई। 1976-77 में रेट आफ ग्रोथ 2 परसेंट रही है। रेट आफ ग्रोथ का टार्गेट जब तक 6, 7 परसेंट नहीं किया जाएगा और जब तक उस के लिये प्लान ऐक्सपेंडिचर जो बढ़ाना चाहिये वह नहीं बढ़ाया जायगा तब तक देश में से 10 साल में पूरी बेरोजगारी समाप्त करने का जो हमारा संकल्प है वह पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये अगले साल के प्लान में इस टार्गेट को बढ़ाना पड़ेगा और रेट आफ ग्रोथ के लिये बोल्ड स्टैप ले कर 6, 7 परसेंट एक वर्ष के हिसाब से करना पड़ेगा।

कुछ दोस्तों ने शिकायत की कि हरिजनों और आदिवासियों के लिये तथा स्लम्स आदि के लिये ज्यादा रुपया नहीं रखा गया है। मैं नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में 5 साल तक मैम्बर रहा हूं, मुझे मालूम है कि सब स्टैट्स इस बात के लिये आग्रह करती रहीं कि जो कुछ भी ग्रान्ट्स, उन को मिलती हैं वह सारी उनको दे दी जाय और स्टैट्स फिर आगे उन को अलग अलग सैक्टर में एलोकेट करेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस पैटर्न को फौरन बदलना चाहिये क्योंकि लम्पसम ग्रान्ट और अलिस्टेम चली जाने के बाद जो स्लम डैवलर्स हैं, वीकर सैक्शन हैं, हरिजन और आदिवासी हैं उन को सब से ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उन को स्टैट्स के अन्दर रुपया नहीं दिया जाता है। इसलिये एक स्पैसिफिक ऐलोकेशन होना चाहिये और स्टैट्स उस के अन्दर खर्च करें तभी उनको पैसा मिलना चाहिये और इसी मद के अन्तर्गत

उस पैसे को स्टट्स खर्च करें। शुरू में यही पटर्न था कि जो रुपया रखा जाता था वह सारा स्टेट्स में हरिजनों और आदिवासियों पर खर्च होता था। लेकिन जब से लम्प सम रूपया स्टेट्स को दिया जाने लगा तब से उस काम पर पैसा खर्च न हो कर अपने अपने क्षेत्रों को लोग फायदा पहुंचाने लगे। इसलिये मेरा कहना है कि इस पैटर्न को चेंज किया जाय और इस प्लान में कुछ रुपया इस के लिये रखें। वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह कुछ पैसा ढूंढ लेंगे अगर स्टैट्स कोआपरेट करने के लिये तैयार हैं तो। लेकिन स्पेसिफिक ऐलोकेशन इस के लिये जरूर हो और स्टट्स को कहा जाय कि यह रूपया इसी मद के अन्दर खर्च करना होगा तभी उन को इस के लिये असिस्टेंस मिलेगी।

मैट्रोपालिटन सिटीज में जो स्लम्स हैं उन के बारे में भी कोई स्पेसिफिक ऐलोकेशन नहीं किया गया। वह जरूर होना चाहिये और जो कांग्रेस सरकार ने कर रखा था कि जो सरकारी जमीन पर स्लम्स हैं उनमें कोरपोरेशन कोई सुधार नहीं कर सकती, इस बैन को कम से कम हटा देना चाहिये। दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, मद्रास में सेन्ट्रल गवर्नमट की जमीनों पर नरक की जिन्दगी बिताने वाले जो लोग हैं उन के अन्दर कोई सुधार करना चाहिये। पहले सुधार करने की कोरपोरेशन या वहां की स्टैट गवर्नमट को इजाजत कांग्रेस सरकार ने बन्द कर रखी थी, जब कि बिजली, पानी, ड्रेनेज आदि देना एक इन्सानी फर्ज बनता है। इसलिये उस बैन को हटा लेना चाहिये और मैट्रोपालिटन फंड की दुबारा स्थापना की जानी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कि दिल्ली के केपिटल रीजन के लिये दिल्ली के आसपास के 40 मील इलाके के विकास के लिये एक केपिटल रीजन फण्ड की भी स्थापना होनी चाहिए और उसके लिये इसमें प्रावीजन किया जाना चाहिये। क्योंकि आसपास की जो स्टेट्स हैं, उनका इन्ट्रेस्ट इस बात में नहीं है कि दिल्ली के आसपास के इलाके का डैवलपमेंट हो। दिल्ली की पापूलेशन इतनी तादाद में न बढ़ सके, जितनी बढ़ रही है, वहां पर इन्फलक्स ज्यादा न हो, उसक लिये जरूरी है कि आसपास के कस्बों और शहरों का पूरा विकास किया जाये। इसके लिए केपिटल रीजन फण्ड की बहुत जरूरत है।

सल्स टैक्स की एबोलिशन इस मुल्क के लिये बहुत जरूरी है। जनता पार्टी के मैनिफैस्टों में भी उसका जिक्र है कि हिन्दुस्तान से सेल्स टैक्स की लानत को खत्म किया जाये। सेल्स टैक्स को खत्म कर के उसको एक्साइज ड्यूटी में कन्वर्ट किया जाये जिस से कंज्युमर को और प्रोड्यूसर को, सब को फायदा हो और करप्शन पूरी तरह से इलीमिनेट हो जाये। इसके लिये मैं यह मानता हूं कि जब तक स्टेट्स नहीं मानेगी, तब तक यह काम नहीं किया जा सकता है। अगर उनको इससे नुक्सान न हो और इस से जो रुपया मिल रहा है वह और किसी रूम में मिल जाय, उसके पास रुपये की कमी हो, तो सेल्सटैक्स को पूरी तरह से एबालिश करने की जरूरत है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि सारे टैक्स के ढांचे पर पुनर्विचार किया जाये। जिस तरह से आज टैक्स हैं, उनको सिम्पलीफाई कर के एक दो टैक्सों में कन्वर्ट किया जाये ताकि न लीकेज हो और न ब्लैक मार्केट हो सके। यह भी जरूरी है कि इन्कम के बजाये एक्सपंडीचर पर टैक्स लगाने की बात सोची जाये। इसको आप कंसोलीडेट कर सकें तो शायद बहुत आसानी इस से हो सकती है यूथ वैलफेयर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर स्पैसेफिक तौर पर कुछ विशेष बातें सामने नहीं रखी गई हैं। कांग्रेस ने पिछले 25, 30 सालों में यूथ वैलवैयर के नाम पर कुछ नहीं किया। हिन्दुस्तान में करोड़ों नौजवान आज बेकार हैं, उनको कोई कंस्ट्रक्टिव एवेन्यूज नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए स्पैसेफिक प्रावीजन जरूर होना चाहिए और अगले बजट में जरूर सोचना चाहिए।

[श्री विजय कुमार मलहोत्रा]

नेहरू युवक केन्द्र बनाए गए थे, उनकी इतनी बुरी हालत हुई कि पार्टी परपज के लिये उनका यूज किया गया। उनको डैन्स आफ करप्शन ऐसी जगह बना दिया गया कि जहां पर एन्टी सोशल काम होते थे। उनका मकसद खत्म हो गया। उसकी बजाए आज नौजवानों के लिए खेल कूद, सोशल सर्विस, आर्ट कल्चर आदि ऐसे कामों के लिये बजट में प्रावीजन करना बहुत जरूरी है। यह अभी हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके बारे में अगले बजट में अवश्य सोचना चाहिये।

अब हिन्दुस्तान को एशियन गेम्स का मौका सन् 1982 में मिल रहा है। पहले हिन्दुस्तान में एशियन गैम्स होते रहे हैं, उसके बाद अब सातवां या आठवीं गेम्स हिन्दुस्तान में यह होने जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस पेस से आज हम चल रहे हैं, अगर उस से ही चलते रहे, जैसे कि पिछले दो साल में इनको नैगलैक्ट किया गया है, तो बाद में हिन्दुस्तान एशियन गेम्स को कर नहीं पायेगा। यह हिन्दुस्तान के लिये बड़ी बेइज्जती और बदनामी की बात होगी कि हिन्दुस्तान को गेम्स एलाट की जाये और वह उनको यहां न कर सके। इसके लिये बजट में कोई एलोकेशन नहीं है, जिसके बिना काम चल नहीं सकता। हमें इसमें एक दिन का भी डिले नहीं करना चाहिये और इसके लिए खास प्रावीजन रखना चाहिए किएशियन गैम्स को हम हिन्दुस्तान में कर सके और उसके लिये जो इन्फ्रा स्ट्रक्चर बनाया जाए उसको पूरा किया जाए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि पावरलूम को जो सुविधा दी गई है, वह मुनासिब नहीं है। पावरलूम को दी गई सुविधा से हैंडलूम इंडस्ट्री तबाह हो जायेगी। बड़ी इंडस्ट्रीज इन पावर लूम का सहारा लेकर इनसे माल बनवायेंगी और इस सुविधा से लाभ उठायेंगी। मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी में यह बात हो गई है। हैंडलूम को प्रोटैक्शन मिलना चाहिए, उसको कभी भी खत्म नहीं करना चाहिये। पावरलूम को जो सुविधाएं दी गई हैं, उनके बारे में पुनर्विचार जरूर करना चाहिए।

इसी प्रकार से चैरिटेबल कार्यों के लिये दान में टैक्स एग्जैम्पशन के सम्बन्ध में दो लाख रुपए की सीलिंग को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर भी विचार करें ताकि इस प्रावीजन का कहीं मिस यूज न हो।

इस बजट में एग्रीकल्चर और खास तौर पर पीने के पानी के बारे में इन्फ्रा स्ट्रक्चर बनाने की नई बातें कही गई हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए परन्तु यह कहना कि इसमें प्रावीजन बहुत कम है, हमारे साथियों को यह समझना चाहिए कि जून के महीने में कोई प्राविजन कर के फरवरी तक उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इस तरह की कोई आइटम जिसकी प्लानिंग न हुई हो, सर्वे न हुआ हो, उसके लिये पैसा रख दे और बाद में बर्बाद हो तो यह ठीक नहीं है। यह बजट रीयलिस्टिक है और जो कुछ इसमें हो सकता था, उसको ध्यान में रखकर बड़ी समझदारी से इसको बनाया गया है परन्तु अगले वर्ष में नया बजट बनाते समय रैडिकल चैन्जेज होनी चाहिये। उस में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिये। कांग्रेस के तीस साल के शासन में बेकारी हर साल भीषण रूप से बढ़ती रही। उस को खत्म करने के लिये हैंडलूम और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज के लिये एलोकेशन होना चाहिये। हमें यह तय कर देना चाहिये कि नेशनलाइज्ड बैंक बड़ी इंडस्ट्रीज को 50 परसेन्ट से ज्यादा लोन नहीं देंगे, और 50 परसेन्ट रूपया छोटी इंडस्ट्रीज को दिया जायेगा जो सेक्टर जितनी एम्पलायमेंट जेनीरेट करता है, उस को उसी हिसाब से रूपया तथा अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिये। अगर स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज 60

परसेंट एम्पलायमेंट जेनीरेट करती हैं, तो 60 परसेंट लोन्ज, स्केयर्स रा मैटीरियल और इम्पोर्ट लाइसेंसिज उन को मिलने चाहिये ऐसा करने पर देश की बेकारी बहुत बड़ी मात्रा में दूर हो सकती है।

बीड़ी पर ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, जिस का असर गरीब आदमियों पर पड़ेगा। यह ठीक है कि बीड़ी पीने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उस से केन्सर होता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इस का उपाय यह है कि लोगों को समझा कर बीड़ी-सिग्रेट पीने से मना किया जाये। जो गरीब लोग इस समय बीड़ी पीते है, इस ड्यूटी के बढ़ने से उन पर बोझ बढ़ जायेगा। इस लिये अच्छा तो यह होगा कि शराब पर ड्यूटी को बढ़ा दिया जाये और बीड़ी को छोड़ दिया जाये।

इन शब्दों के साथ में वित्त मंत्री को यह बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं। कांग्रेस के शासन में देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी और डिसपैरिटीज बढ़ती रही हैं। उन को दूर करने के लिये वित्त मंत्री ने एक दिशा-निर्देश किया है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष इस सम्बन्ध में रैडिकल चेंजिज की जायेंगी।

SHRI VENUGOPAL GOUNDER (Wandiwash): Sir, I would be failing in my duty if I do not congratulate the Prime Minister and the Agriculture Minister for giving due consideration to the rural economy. Hitherto much was claimed as having been done for the agriculturists, but in actual practice, the statistics show that the benefits given by way of loans, aid etc. to industries, both small and medium and big, have been much more than the benefits given to the agriculturists. It is a big question mark whether even the benefits given to intended agriculturists actually have reached the intended persons—the small and medium farmers and the marginal farmers—who are actually engaged in agriculture. In the past, the tillers of the land have not enjoyed the benefits. The big landlords got the fruits of the benefits. This may be due to poverty, illiteracy and other factors. I request the government to plan in such a way as to enable the benefits to reach the real tillers of the land—medium or small and the marginal farmers. Then only we can improve agricultural production.

Another problem facing the agriculturists is the lack of marketing facilities. The industrialists are in a position to fix the prices of the products they produce but the agriculturist is not in that position. He is at the mercy of the middlemen who know nothing about agriculture. The government should fix the prices in such a way that they are economical to the farmer. I suggest that regulatory marketing committees should be established in each and every village. The agriculturists must get reasonable price for his produce. If the market prices are low, the government should not hesitate to purchase the produce at a reasonable price and build up buffer stocks. Otherwise, the poor agriculturists are at the mercy of the middlemen who are exploiting

[Shri Venugopal Gounder]

the situations. So, I request the Government to see that each and every village should have a regulatory market.

There is another aspect which I would like to touch. Suppose there is a bumper harvest. The theory of supply and demand will operate fully. The producer in the industrial sector is in a position to create an artificial demand so that he is in a position to get more money whereas the agriculturists is not in a position to do so. If the regulated market is operated, then something could be done.

Another important aspect is the distribution of fertilizers to the agriculturists. During the past two years all of a sudden the price of fertilizer Urea had gone up. Without relation to the cost of production of agricultural produce, the prices of fertilizer have gone up. So, the prices of fertilizers should be reduced and they should be distributed to the agriculturists. For proper distribution of fertilizer, it is better that fertilizers are distributed through cooperative agencies or panchayats so that they can be given to needy persons without any delay.

As far as Tamil Nadu is concerned, we are mostly dependent on the vagaries of the monsoon. Sometimes no water is available. Even the available water is subjected to dispute. There is a longstanding dispute between Tamil Nadu and Karnataka relating to Cauvery waters. So the dispute should immediately be settled. I hope the Centre is interested to see that it is amicably settled.

I would like to suggest that river waters in the country should be treated as a national asset. If the river waters become a national asset, then disputes can be averted.

I would like to state that for agriculture, as far as Tamil Nadu is concerned, we are subject to power cuts. The former Chief Minister Mr. Karunanidhi without considering all the aspects diamantled the Samayanallor power plant. He has not constructed another power plant after dismantling it. So we are suffering a lot. Every village in Tamil Nadu is experiencing a power cut for about six months in a year. So, I would like to suggest that as far as agriculturists are concerned, they may be exempted from this power cut. If the power cut is imposed in respect of small and marginal agriculturists, they will be put to a lot of suffering. So, I would like this Government to advise the electricity boards of all State Governments to exempt agriculturists from imposition of power cuts.

श्री यू० एस० पाटिल (लातुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, जनता पार्टी के वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने सही कहा है कि बजट एक ऐसा साधन है जिस से यह ज़ाहिर होता है कि जो आइन्दा आने वाला समाज है, वह किस तरह से प्रस्थावित होगा । यह सही है कि पिछले तीस सालों में देश में कांग्रेस सरकार ने समाजवादी समाज की रचना या समाजवाद लाने की घोषणायें तो की थीं, लेकिन उनकी जो सब से आखरी घोषणा हुई "गरीबी हटाओ", उस को लोगों ने पकड़ लिया कि हम गरीब रहना नहीं चाहते हैं । यह एक बड़ी अच्छी चीज़ है और मौजूदा हुकूमत को आगे खींचने वाली एक ड्राईविंग-फोर्स साबित होगी । लेकिन जैसा मेरे माननीय मित्र मल्हौत्रा जी ने कहा, बल्कि आंकड़े देकर स्पष्ट किया—उन घोषणाओं से समाजवाद तो नहीं आया, लेकिन मौनोपोलिस्टिक इण्डस्ट्रीज़ देश में पैदा हो गई । इस देश में पिछले दिनों में इण्डस्ट्रीयल बैल्ट बहुत बढ़ी है, इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आपात-स्थिति के जो आंकड़े बजट में कांग्रेस सरकार ने रखे थे, उस में बहुत ज्यादा कल्सेशन उद्योगपतियों को दिया गया, न सिर्फ इस देश के उद्योगपतियों को, बल्कि अमरीका, जर्मनी और दूसरे देशों के उद्योगपतियों को बुला कर यहां इन्वैस्ट

करने के लिये कहा गया । मल्टी-नेशनल कार्पोरेशन्ज को इन्वीटेशन देकर यहां इन्वैस्ट करने के लिये उस कांग्रेस सरकार ने कोशिश की और जब मोनोपोलिस्ट्स कहीं आम-जाते हैं, थोड़े से लोगों के हाथों में जब पूरी इकानमी चली जाती है तो उस का परिणाम होता है—बेरोजगारी, इन्फलेशन, बेकारी, गुरबत—ये सब चीजें बढ़ जाती हैं ।

आज हमारे देश में यही हालत है—समाजवाद का नाम लिया, लेकिन गुरबत बढ़ी । "जोतनेवाले की जमीन" का स्लोगन दिया गया, लेकिन 1961 से 1971 तक की रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिये, देश में मजदूरों की तादाद बढ़ गई है, वे अपनी जमीन को खो बैठे हैं, जोतनेवाले जमीन पर नहीं रहे, वे मजदूर बन गये । आज जनता पार्टी के सामने यही प्राब्लम है । जनता पार्टी किसानों के लिये बहुत कुछ करना चाहती है—लेकिन देहाती जनता को अभी विश्वास नहीं है । जब तक कोई चीज वास्तविक रूप में उन के सामने न हो, उन को रिअलाइज नहीं होता है कि कोई चीज हो रही है । इसी लिये समाजवाद के नाम के साथ-साथ आज गांधी जी के सिद्धान्तों की घोषणायें हो रही हैं । लेकिन मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि हमें सिद्धान्तों के झगड़े को छोड़ देना चाहिये, कुछ वास्तविक रूप में कर के दिखाना चाहिये । आप देखिये—डी-सेन्ट्रलाइज्ड इकानमी कांग्रेस का आदर्श था, लेकिन वह डी-सेन्ट्रेलाइज नहीं हुई, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सैन्ट्रलाइज होती रही । गांधी जी का सिद्धान्त है कि विलेज सेल्फ-रिलायेंट रूरल कम्यूनिटी बने—इस बात की घोषणा वित्त मंत्री जी ने भी की है । लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे विलेजेज की 40 परसैन्ट पौपुलेशन बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों—बम्बई, दिल्ली, कानपुर जैसे शहरों में जा रही है । आज छोटे किसान और मार्जिनल फार्मर्ज की यह हालत है कि वे जमीन रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बैंकों से उन्हें कर्जा नहीं मिलता है और अगर कहीं मिला भी है तो बहुत थोड़ा मिला है । 65 परसेन्ट जो हमारे छोटे किसान हैं, जब तक उन की उपज नहीं बढ़ती है, तब तक उन को जमीन पर काम करने से कोई फायदा नहीं होगा । उन के लिये फाइनेंस का इन्तजाम होना चाहिये, मार्केटिंग का इन्तजाम होना चाहिये, इन्पुट्स के लिये पैसा दिया जाना चाहिये—जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी हमारे देश की इकानामी बढ़ नहीं सकती । इस बजट में भी यही कमी है; आप ने घोषणा की है कि हम देहातों में जो कम पैसा दिया जाता है, उन को अधिक देंगे, हम खेती को बढ़ाना चाहते हैं, छोटे किसानों को आगे लाना चाहते हैं । वित्त मंत्री के भाषण के हर पैराग्राफ में इस बात को काफी जगह दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो लेबर मूवमेन्ट हो रहा है, बड़े बड़े शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं उस की वजह से हमारी खेती की इकानमी बरबाद होती जा रही है । यह आज से नहीं है—पिछले 30 सालों का नतीजा है । कांग्रेस के पिछले मिनिस्टर्ज और आज के फाइनेन्स मिनिस्टर देखें—यह उन्हीं की लैगेसी है, इस को बदलने की उम्मीद हम करते हैं, जनता पार्टी की कोशिश है कि इस को बदला जाय, लेकिन बदलते वक्त भी इस बजट स्पीच में जो रखा गया है—मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जो घोषणा की गई है, वह किसान को मिल सकेगा ।

अगर आप सरकारी क्षेत्र में जो उद्योग हैं, उन को कम पैसा दें, अगर आप छोटी मछली को बड़ी मछली द्वारा खाने का सिद्धान्त फिर अमल में लाना शुरू कर दें और सिक यूनिट को बड़े यूनिट में मर्ज होने के लिए इन्वेस्टमेंट में कुछ कन्सेशन्ज दें, तो यकीनन इस मुल्क में मोनोपली के ट्रेंड बढ़ जाते हैं । अगर आप का बजट मुट्ठी भर लोगों के, अपनी आमदनी का बहुत बड़ा भाग 10 पर सेन्ट लोगों के हाथों में दे देते हैं, तो 90

[श्री यु० एस० पाटिल]

पर सेन्ट लोगों में गुरबत आ जाती है ।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन को कम करने के जो तरीके इस बजट में अपनाये गये हैं, वे कोई नये तरीके नहीं हैं । रिजर्व बैंक की तरफ से क्रेडिट स्क्वीज की जाती है या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बैलैंस रखा जाता है, तो ऐसे मेजर्स वेस्टर्न कन्ट्रीज कई मर्तबा अपना चुके हैं लेकिन उनके कोई रिजल्ट्स नहीं निकले हैं । जब श्री सी० डी० देशमुख फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उस वक्त से यह होता चला आ रहा है कि जब कोमोडिटी महंगी हो जाती है, तो रिजर्व बैंक बैंकों को आर्डर करता है कि इतना क्रेडिट कम कर दो और फला फला चीज कर दो । पांच, छः महीने में मार्केट एडजस्ट हो जाता है लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है । इमर्जेंसी के जमाने में आपने देखा कि 5, 6 महीने कुछ चीजें डाउन आ गई और वे भी एग्रीकल्चर कामोडिटीज लेकिन इन्डस्ट्रियल कामोडिटीज पर कोई खास असर नहीं पड़ा और वे बढ़ती गई । इस तरह से ये जो मेजर्स लिये गये हैं ये कोई नये नहीं हैं और वही पुराने तरीके हैं जिन को कांग्रेस पिछले 30 सालों से अपनाती आ रही है । अगर जनता के फाइनेन्स मिनिस्टर उन्हीं मेजर्स पर अपनी इमारत रखेंगे, तो मैं नहीं समझ सकता कि इन्फ्लेशन को आप कम कर सकते हैं ।

एक दूसरी बुनियादी चीज यह है कि हमारे मुल्क में छोटे किसानों का बहुत बड़ा मसला है और सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी है । किस तरह से इस को बढ़ाएं, यह देखने की बात है । न सिर्फ यही, बल्कि बैंकिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है । आज किसान को खेती के कामों के लिए बैंकों से इतना कर्जा नहीं मिल पाता कि वह उस में उन्नति कर सके । इस के अलावा मार्केटिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है । मार्केटिंग में हायस्ट एक्सप्लायटेशन अगर किसी प्रोफेशन का है, तो वह किसानों का है । जब तक इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और कैपिटल फार्मेशन नहीं होता है, तब तक यह धंधा आगे नहीं बढ़ सकता है । इंडस्ट्रीज में अगर किसी चीज में नफा नहीं होता है, तो वह सरकार के लिए सिर दर्द हो जाती है । मालिक उस को बन्द कर देता है और कोई दूसरा काम करने लगता है लेकिन किसान का ऐसा प्रोफेशन है कि अगर उस को अपने धंधे में नुकसान भी रहता है, तो भी वह उस को नहीं छोड़ सकता और वह हमेशा सिक रहेगा । अगर उस का प्रोडक्शन जीरो भी हो जाता है, तो भी वह उस धंधे को क्लोज नहीं करता लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी एकोनामी पर पड़ता है । आप के पास कपड़ा है और यहां पर ग्राहक नहीं है, तो आप उस कपड़े को अमेरिका और इंगलैंड भेज देते हैं लेकिन किसान की पैदावार के लिए ऐसा नहीं होता है । अगर उस की प्रोडक्ट के लिए मार्केट नहीं है या ग्राहक नहीं है, तो उस को नुकसान उठाना पड़ता है और इस तरह से उस की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है । इस तरह से 70 और 80 फीसदी धंधा जो खेती का है, वह इन 30 सालों में बर्बाद हो चुका है और कांग्रेस सरकार के जमाने में उन के सिद्धान्त चाहे जो भी रहे हों और चाहे जो भी घोषणाएं हुई हों, किसान हमेशा बर्बाद होता रहा है ।

देहातों में अनएम्पलायमेंट बहुत बढ़ गया है । अर्बन में भी यह बढ़ गया है और इस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप के जो ग्रेजुएट और मेट्रीकुलेट लड़के हैं और जो खेती के काम में लगे हैं और जिन के पास तीन, चार या पांच एकड़ जमीन है, उन को सेल्फ एम्पलायमेंट की स्कीम में सौ फीसदी कर्जा देने के लिए आप सोचिये । अगर उस को एक तहसीलदार या दूसरी गजेटेड पोस्ट की तनख्वाह के बराबर उस में इन्कम हो जाती है, तो वह भी शहरों में नौकरी करने के लिये नहीं आएगा । उस को एम्पलायमेंट देने का एक ही जरिया है कि बैंक 100 फीसदी कर्जा उसे दें और कम सूद

पर वह कर्जा दिया जाए और 15, 20 इंस्टालमेंट्स में उस का पेमेंट हो। इस के अलावा जो वह पैदा करता है, उस में उस को 15 पर सेन्ट का फ़ायदा हो, तो आप की अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम कुछ सोल्व हो सकती है। इस तरह से जो छोटे किसान हैं, उन के लिए सैल्फएम्पलायमेंट की स्कीम होने की बहुत आवश्यकता है।

जापान की मिसाल यहां पर दी जाती है। बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जापान में जो सीलिंग है, वह एक यूनिट की 7 एकड़ की मैक्सीमम सीलिंग है। हमारे देश में सीलिंग का झगड़ा अभी भी चल रहा है। आज अगर एक किसान के पास 100 एकड़ जमीन भी है, तो भी उसको खाने को नहीं मिलता है। एक एक किसान के पास 25, 25 और 50, 50 एकड़ जमीन होने पर भी कोई ज्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनटेंसिव कल्टीवेशन अगर हो, तो अच्छा है और जमीन की सीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि यह देखा जाए कि एक फैमिली में खेती करने की कितनी कुव्वत है। उसी हद तक आप सीलिंग रखें। इसलिए इस सबन्ध में मैं यही कहूंगा कि दो चीजें आप किसान को जरूर दीजिए, एक तो बैंकिंग फैसिलिटी और दूसरे उसके सामान के लिए मार्केट। जापान कम्युनिस्ट देश नहीं है। उसमें भी 45 के बाद से सात एकड़ जमीन पर सीलिंग है। लेकिन एक एकड़ में हिन्दुस्तान में जितनी मैन पावर लगी है, उससे चार गुना मैन पावर को एम्प्लायमेंट देने की उसमें कुव्वत है। हमारे देश में भी इतनी कुव्वत है लेकिन हमारे देश में प्लान बनाने वाले, प्लानिंग कमीशन यह गलत समझ बैठे हैं कि हम इतनी पापुलेशन को धंधा नहीं दे सकते हैं। वह पापुलेशन को इस तरह से तकसीम कर देते हैं कि अगर पानी होगा तो हम इतने लोगों को धंधा दे सकेंगे, अगर पावर होगा तो इतने लोगों को धंधा दे सकेंगे। अगर हम खेती में इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं तो हम दस गुना लोगों को एम्प्लायमेंट दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लान बनाते समय हमें खेती को अधिक एम्प्लायमेंट देने का साधन बनाना चाहिए। हमें अपने मुल्क के गरीब किसानों और मार्जिनल फार्मर्स की इन्कम भी बढ़ानी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि एक मजदूर को कम से कम पांच से दस रुपए रोजाना मजदूरी मिलनी चाहिए। जब हम देहात में कोई इण्डस्ट्री चलाते हैं, शुगर इण्डस्ट्री लगाते हैं या टैक्सटाइल इंडस्ट्री लगाते हैं तो कम से कम उसको पौने दो सौ या डेढ़ सौ रुपया महीना मिल जाता है। जो भाई गन्ने को पानी देता है उस बिचारे को दो से तीन रुपए रोज मिलता है। इस हालत में तो खेती करने वाले को मजदूर मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज मजदूर की कमी है। अगर आप चाहते हैं कि इरीगेटेड ट्रेक्स के लिए मजदूर मिलता रहे तो आपको अनएजूकेटेड या एजूकेटेड बेकारों को खेती की ओर बढ़ाना चाहिए।

दूसरी चीज, महाराष्ट्र में एक अच्छी चीज हो रही है। वहां एम्प्लायमेंट गारण्टी स्कीम चालू है। इस स्कीम को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें काफी खामियां और त्रुटियां हैं। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के लोगों के हाथ में पावर होने से उसमें अच्छी तरह से काम नहीं लिया जाता। इस स्कीम से हम लोगों को बारह महीने काम दे सकते हैं। कहने वाले लोग कहते हैं कि किसान और मजदूरों के हाथों में पैसा देने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसके मायने क्या हैं? किसान को उसकी तनख्वाह मिल गयी तो इंफ्लेशन बढ़ता है और अगर इस फिलासफी को लेकर हम चलते हैं तो उसको क्या हम मार्जिनल किसान ही रखना चाहते हैं? क्या हमने प्लानिंग इसलिए की है कि गरीब किसान को हम उसका हक न दे सकें, उसको सामर्थ्यवान न बना सकें? वह भी इस मुल्क की जमीन का मालिक बने, कारखाने का हिस्सेदार बने। अगर आप

श्री यू० ए० स० पाटिल : सही मायने में गांधी फिलासफी को जानते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि इस देश की जमीन के मालिक सभी लोग हैं, गांव की जमीन का मालिक गांव का आदमी है । यह मुल्क इस देश की जनता का है । मुझे डर है कि जनता पार्टी में भी जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के लोग हैं वे अपने मफ़ाद के लिए गांधीवाद को न चलने देंगे । इससे देश की बर्बादी होगी । हमारा समाज सभी लोगों का है, यह मुल्क भी सभी लोगों का है, इसलिए हमें सभी लोगों को काम देना है । जितने भी इस देश में तालीम याफ्ता नौजवान हैं उन सभी को काम में लगाना है । गांव के हर आदमी को काम में लगाना है । मुझे इस बात की खुशी है कि इलेक्शन के बाद से देश का नौजवान अपने सवालात को हल करने के लिए खड़ा हो गया है ।

अब मैं इस बजट की दो-तीन खामियों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । इस वक्त उसके लिए प्राविज़न आपने बहुत कम किया है । अगले साल आप क्या करते हैं इसको देखेंगे । आपको ऐसे कदम उठाने चाहियें ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सके । देश में प्रोडक्शन जो होता है उसको वे खरीद सकें, उसको बढ़ावा मिले । वर्ना हालत खराब हो जाएगी । आज क्या हो रहा है । काटन आप बाहर से मंगा रहे हैं, तेल आप बाहर से मंगा रहे हैं, अनाज बाहर से मंगा रहे हैं और जो चीज़ें यहां पैदा होती हैं वे यहां बिकती नहीं हैं और उनको बाहर भेजने की कोशिश की जाती है । यह गलत इकोनोमी है । जो कच्चा माल हम को कारखानों के लिए चाहिए वह हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा ादा होना चाहिए तभी हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वह मजबूत हो सकता है, पक्का हो सकता है । ऐसा न होने से क्या होता है ? दस नई इण्डस्ट्रीज़ जो स्थापित हो सकती थीं वे स्थापित नहीं होती हैं और इसके बजाय पन्द्रह सिक यूनिट्स की श्रेणी में चली जाती हैं और जब जमा और खर्च का हिसाब लगाया जाता है तो पता चलता है कि हम नुकसान में गए हैं, घाटे में गए हैं । लोगों को आप रोज़गार देने की व्यवस्था करें, उनके लिए काम धंधे देने की व्यवस्था करें, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएं, सत्तर परसेंट पापुलेशन जो है उसकी तरफ आप विशेष ध्यान दें, उसका स्तर ऊंचा करें, यही मुझे आप से निवेदन करना है ।

श्री लक्ष्मण राव मानकर (भंडारा) : अर्थ मन्त्री महोदय ने अपने बजट में कुछ बातों को दिशा देने का प्रयास किया है । प्रमुख रूप से उन्होंने बताया है कि इस देश में तीस साल तक जो प्लानिंग हुआ है उस प्लानिंग की वजह से बहुत सी खराबियां पैदा हुई हैं, महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है । डिफिसिट फाइनेंसिंग करने से हमेशा महंगाई बढ़ती है । इस वास्ते इसको कम करने का प्रयास इस बजट में किया गया है । कुछ बातें इसमें दिशा के रूप में दर्शाई गई हैं । मैं मानता हूं कि कई मदें ऐसी हैं जिनमें और अधिक प्राविज़न करने की आवश्यकता थी । मैं मानता हूं कि जो भी प्राविज़न विभिन्न मदों में किए गए हैं वे काफी नहीं हैं । लेकिन जो एक दिशा, निदेश मन्त्री महोदय ने किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए ।

मैं कांग्रेस मित्रों के भाषण सुन रहा था । उन्होंने कहा है कि बजट में स्माल फार्मर्ज़ स्कीम के लिए एग्रीकल्चर लेबर आदि के लिए बहुत कम प्रोविजन किया गया है । मैं मानता हूं कि इसको बढ़ाया जा सकता था । दूसरी मदों पर भी खर्च को बढ़ाया जा सकता था । लेकिन आप देखें कि पिछले साल के बजट में एग्रीकल्चर लेबर के लिए जहां 26 करोड़ का प्राविजन किया गया था इस साल के बजट में 46 करोड़ का किया गया है । ज्यादा प्राविज़न करने का इसमें प्रयास किया गया है । लेकिन ऐसा डिफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ा कर ही किया जा सकता था । कांग्रेस शासन ने पिछले अनेक वर्षों में डिफिसिट फाइनेंसिंग

को खूब बढ़ाया है । ऐसा हम भी कर सकते थे । लेकिन हमने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा ।

यह भी कहा गया है कि स्टेट सैक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है । आप देखें कि भिलाई कारखाने के लिए प्राविजन बढ़ा दिया गया है । कारण यह है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर आगे बढ़े । जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल है, वहां बेकारी का सवाल है, खेतीहर किसानों का सवाल है, उनके बारे में इस बजट में एक दिशा देने का प्रयास किया गया है । एग्रीकल्चर बेस्ड और फारेस्ट बेस्ड इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले इस बात की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया । यह बहुत सफ़िशियेंट है ऐसा मैं नहीं मानता हूं । किन्तु कुछ बातों की तरफ़ ध्यान देने की आवश्यकता है । जैसे कि जंगलों में अनेक चीजें पैदा होती हैं, मिसाल के लिए लाख है जो जंगलों में पैदा होती है जिसकी वजह से लोगों को उद्योग और जो मजदूरी मिलनी है वह काफ़ी नहीं है । बहुत कम मात्रा में उनको मजदूरी मिलती है । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को, जो लाख का काम करते हैं, तीन रुपया देने की बात कही । लेकिन तीन रुपया किसानों को कभी नहीं मिला । लाख से हम को फ़ौरेन एक्सचेंज मिलती है । किन्तु अनेक प्रान्तों में अलग अलग प्रकार की नीति आदिवासियों और गरीबों के लिए रखी जाती है । जिन लोगों का जीवन ही जंगलों मे पैदा होने वाली चीज़ों पर चलता है उन पर ऐसे नियंत्रण डाले गए है जिसकी वजह से आदिवासी लोगों को और जंगलों में रहने वालों को कोई लाभ नहीं मिलता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue later because at two O'clock, we have to take up Calling Attention. Shri Chitta Basu.

---

14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PRE-ELECTION POLITICAL SITUATION IN JAMMU & KASHMIR AND POSTPONEMENT OF THE ASSEMBLY ELECTION.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I call the attention of the Minister of Law, Justice and Company Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Pre-election political situation in Jammu and Kashmir and reported postponement of the Assembly election scheduled to be held from June 30 to July 3, 1977."

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Deputy Speaker, Sir, Elections to the Legislature of Jammu and Kashmir are held under the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir and the laws made thereunder. The functions of the Election Commission of India also extend to the elections to the State Legislature. It is open only to the Election Commission to postpone the dates of polling by a notification under section 155 of the Jammu & Kashmir Representation of the People Act, 1957 for reasons which it considers sufficient. As it is, the elections to the State Legislative Assembly are scheduled to be held on June 30, July 2 and 3. These dates were fixed by the Election Commission of India under section 41 of the J & K Representation of People Act, 1957.

There has been considerable resort to violence in the Kashmir Valley in the course of the election campaign for some time now. Several clashes have already taken place between rival political groups.

The present series of incidents of disorder started with Shri Sheikh Abdullah's entry into the Valley early